

दैनिक बढ़ता राजस्थान

संस्करण : जयपुर, टोंक, अलवर एवं कोटा

Since : 2004

/// कदम बढ़ाएं, सच के साथ

वर्ष : 15 | अंक : 238

जयपुर | बुधवार, 02 जुलाई, 2025 | आषाढ़, शुक्रवार कक्ष सप्तमी संवत्-2082

भारत व राज्य सरकार से विज्ञापनों के लिए स्वीकृत

| मूल्य : ₹ 5.00 | पृष्ठ : 10

सरकार ने कहा- हम एसआई भर्ती रद्द नहीं करेंगे

कैबिनेट सब-कमेटी ने रद्द नहीं करने की सिफारिश की, सीएम ने माना; 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई

बढ़ता राजस्थान

जयपुर (कास.)। राज्य सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं करेगी। एडवोकेट जनरल (एजी) राजेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट सब-कमेटी को रिपोर्ट एडिशनल एफडीटी के साथ भर्ती में रखी। प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है। जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने अप्रूव किया है। इसके दोषी पक्षों की निर्देश दिए। 7 जुलाई को काइन्स सुनवाई होगी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि हम इस स्टेज पर भर्ती को रद्द नहीं कर सकते हैं। अंतिम महाधिकारी विज्ञान शाह ने बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी ने चार सिफारिश की।

याचिका का सार्वीन मानते हुए खारिज किया जाए

चप्पनित अध्याधियों की ओर से बिरुद्ध एडवोकेट आरएन माथुर ने कहा कि सब कमेटी की रिपोर्ट कहीं है कि आगे भर्ती को रद्द किया जाए है तो बड़ी संख्या में निर्देश अध्याधियों की साथ कुठारवात होगा। हमने कोट को यह भी कहा है कि याचिका में एसआईटी सहित सरकार की पिछले सभी रिपोर्ट के चुनौती दो गई हैं। हालांकि अब सरकार की ओर से नई रिपोर्ट योग की गई है, जिसे याचिका में चुनौती



अब तक क्या-क्या हुआ...

- एसआईसी ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर व प्लाटारून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती निकाली थी।
- भर्ती परीक्षा में पैरोल लिंक के आरोप लगे, सरकार ने जांच स्वाक्षर की दी।
- एसआईसी ने दोनों स्ट्रीट कोट के आरोप लगे, सरकार ने जांच स्वाक्षर की दी।
- याचिकाकर्ताओं के बालौन हाईकोर्ट ने बताया-जरिटिस सर्वीज जैन की अदालत में 18 नवंबर, 6 जनवरी और 9 जनवरी को पूरी भर्ती प्रिक्षिया पर यथास्थिति को चारों दिन दिया है।
- हाईकोर्ट की एकाधिकारी ने आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी 2025 को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फॉल ट्रैनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक आज भी जारी है।

वकील मेजर आरपी सिंह और हॉटेंड्र नील ने कहा कि सरकार अपने पावर का मिस यूके कर रही है। पले यही सब कमेटी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करती है और अब यही कमेटी भर्ती को जारी रखने की सिफारिश कर रही है।

राजकार पावर का मिस यूके कर रही

वर्ती सरकार की रिपोर्ट पर याचिकाकर्ताओं की ओर से बिरुद्ध

26 मई को सरकार ने कोट में कहा था- हम निर्णय लेना चाहते हैं

दरअसल, 26 मई को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में कहा था- हम भर्ती पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं। जब मुझसे ऑपरेशन योगी ने गई थीं तो मुझे बताया गया था कि भर्ती में 400 से 500 लोग लिस हैं। एसआईसी अभी तक केवल 55 लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। भर्ती में 800 से ज्यादा अध्याधियों के भविष्य का सवाल है।

कोट ने सवाल किया था कि सरकार को निर्णय लेने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस पर महाधिकारी ने कहा था- सीएम के सरपर निर्णय होना है, ऐसे समय दिया जाए। वर्ती, याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि चार-वार एजेंसिया भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर बुझी है। पिछे भी सरकार निर्णय लेने में देरी कर रही है।

कोट ने सवाल किया था कि एसआईसी को सब-कमेटी की मीटिंग बुझाई थी।

ऑपरेशन सिद्धूर के बलते कई मंत्री बैठक में शामिल हो गए।

सरकार की एक बैठक में शामिल होने के बलते नहीं पहुंचे थे।

पिछली बार कोट में कहा गया था कि सरकार ने 21 मई को सब कमेटी को बैठक रखी है। इसमें जो भी फैसला होगा। कोट को अवगत कराया जाएगा।

मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा उधार ले रहे हैं। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अन्य रिटेल लोन शामिल हैं।

नॉन-हाउसिंग रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया में सबसे ज्यादा बढ़ोतारी हुई है। ये लोन टोटल डोमेस्टिक लोन का 54.9% हिस्सा है।

हर भारतीय पर 4.8 लाख का कर्जदार

दो साल में 90 हजार रुपए बढ़ा

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में यह 3.9 लाख रुपए था। बैते दो साल में इसमें 23 लक्ष की बढ़ोतारी हुई है। यानी, हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्ज और बढ़ गया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जून 2025 की फाइनेंशियल स्ट्रेटिजी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।

सवाल 1- कर्ज बढ़ने का मतलब क्या है?

जबाब-इसका

को डिस्ट्रिक्ट इनकम (खर्च करने योग्य आय) का 25.7% है। हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है और इसमें भी ज्यादातर दुनका है जो पहले कर्ज का स्तर बढ़ा जाता है।

जबाब : RBI के मुताबिक भारत के कुल जीडीपी का 42% कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) से ज्यादा भारत में कर्ज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। यानी, भारत में कर्ज की अवधि एजेंसी रिपोर्ट में बढ़ गया है।

जिवाब बैंक ने कहा है कि इस कर्ज से फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतर रेटिंग वाले हैं। वे कर्ज चुकाने में सक्षम हैं।

साथ ही, कोविड-19 के समय की तुलना में डेलिक्टेन्से रेट यानी कर्ज न चुका पाने की रेट में कमी आई है। हालांकि जिन लोगों की रेटिंग कम है और कर्ज ज्यादा है, उनके लिए थोड़ा जोखिम है।

सवाल 2- क्या GDP के मुकाबले देश में कर्ज का स्तर बढ़ा जाता है?

जबाब-माइक्रोफाइनेंस सेक्टर (छोटे लोन प्याए) में कर्ज लेने वालों की एवरेज रेट में कमी आई है। हालांकि जिन लोगों की रेटिंग कम है और कर्ज ज्यादा है, उनके लिए थोड़ा जोखिम है।

सवाल 3- माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में कर्ज की स्थिति कैसी है?

जबाब-माइक्रोफाइनेंस सेक्टर (छोटे लोन प्याए) में कर्ज लेने वालों की एवरेज लायबिलिटी 11.7 लक्ष तक कम हुई है, लेकिन 2025 की दूसरी छामाही में स्ट्रेस असेंट्स की संख्या बढ़ी है। आरबीआई ने कहा है कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियां ज्यादा ब्याज दें और मार्जिन ब्यूलूर हो रही हैं। जो कर्ज लेने वालों के लिए चुका पाना मुश्किल हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में पहली बार उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम, एससी/एसटी कर्मचारियों को मिलेगा 22.5% कोटा

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। गडकरी ने हमले को जघन्य और गंभीर रूप से निर्देशन दिया है। यह व्यक्ति पर अनुकरणीय कार्रवाई की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य सार्वजनिक संस्थानों और कई उच्च न्यायालयों के साथ खुद को जाड़ते हुए ऐसी नीति अनाई है।

सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-सार्वी भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आधिकारिक तौर पर आकर्षण नीति लागू की है। यह कदम पहली बार है जब सर्वोच्च



न्यायालय ने अन्य सार्वजनिक संस्थानों और कई उच्च न्यायालयों के साथ खुद को जाड़ते हुए ऐसी नीति अनाई है।

एससी-एसटी आकर्षण अब एससी स्टाफ नियुक्टियों में प्रभावी

24 जून, 2025 को सुप्रीम कोर्ट के सभी कर्मचारियों को जारी है। एक परिचय में नई आकर्षण नीति लागू हो जाएगी।

सुधार की अगुआई की

भारत के मुख्य न्यायालयी

डीवाइंस एंड्रॉडूट के बाद गोपनीय आरक्षण वहाँ हो जाएगा।

आरक्षण के बाद गोपनीय आरक्षण वहाँ हो जाएगा।

आरक्षण के बाद गोपनीय आरक्षण वहाँ ह

